

"RIGHT TO EDUCATION ACT (2009)" A PRACTICAL INQUIRY AT THE TEACHER LEVEL AND ITS COMPREHENSIVE DEVELOPMENT IN PRIMARY EDUCATION

शिक्षा का "अधिकार अधिनियम (2009)" शिक्षक स्तर पर एक व्यवहारिक जांच और प्राथमिक शिक्षा में इसका व्यापक विकास

Rafiq Ali¹ and Dr. Suresh Kumar Jat²

¹Research Scholar, Mansarovar Global University, Sehore (M.P)

²Research Supervisor, Mansarovar Global University, Sehore (M.P)

ABSTRACT

The investigators examined the attitudes of students and teachers towards the "Right to Education Act, 2009" or the "RTE Act, 2009," and how many areas in the education sector can be applied to this act according to the teachers' point of view. The investigation was conducted in the Shivpuri district of Madhya Pradesh. For this study, the researcher used the descriptive survey method. The organisation is using 150 teachers from 20 (twenty) government secondary schools in the Shivpuri district of Madhya Pradesh. The collection was selected using the survey method. The researchers developed their own survey to assess teachers' perceptions of the Right to Education Act 2009 and its implementation in the educational environment. The investigators used a basic percentage technique to analyse the data item by item. The overall findings suggest that the attitudes of secondary school teachers differed by issue. Secondary school teachers have expressed their opposition to certain items related to the RTE Act, 2009 as well as some items related to the RTE Act, 2009. This is represented in the present study.

जांचकर्ताओं ने "शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 या आर्टीई अधिनियम, 2009" पर छात्रों और शिक्षकों के दृष्टिकोण की जांच की और शिक्षकों के दृष्टिकोण के अनुसार इस अधिनियम में कितने क्षेत्रों को शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया जा सकता है जांच मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में की गई। इस अध्ययन के लिए शोधकर्ता ने वर्णनात्मक सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया है। संगठन मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में 20 (बीस) सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के 150 शिक्षकों का उपयोग कर रहे हैं। संग्रह का चयन सर्वेक्षण विधि का उपयोग करके किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और शैक्षिक वातावरण में इसके कार्यान्वयन पर शिक्षकों की धारणाओं का आकलन करने के लिए शोधकर्ताओं ने अपना स्वयं का सर्वेक्षण विकसित किया। जांचकर्ताओं ने आइटम के आधार पर डेटा आइटम का विश्लेषण करने के लिए एक बुनियादी प्रतिशत तकनीक का इस्तेमाल किया। समग्र निष्कर्ष बताते हैं कि माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के दृष्टिकोण मुद्दे के आधार पर भिन्न थे। माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों ने आर्टीई अधिनियम, 2009 से जुड़ी कुछ वस्तुओं के साथ-साथ आर्टीई अधिनियम, 2009 से संबंधित कुछ मदों के लिए अपना विरोध व्यक्त किया है। वर्तमान अध्ययन में इसका प्रतिनिधित्व किया गया है।

Keywords: व्यवहार, शिक्षक, शिक्षा का अधिकार, आर्टीई अधिनियम (2009), बुनियादी प्रावधान, व्यावहारिक कार्यान्वयन, स्कूली शिक्षा।

1. प्रस्तावना

1.21 बिलियन निवासियों के साथ, भारत देश का सबसे बड़ा कार्यशील लोकतंत्र है (भारत की जनगणना रिपोर्ट, 2011)। हालांकि, सरकार की गंभीर चुनौतियों में से एक यह है कि 42.1 प्रतिशत आबादी शिक्षा असमानता (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम - यूएनडीपी, 2014) से वंचित है। एक कारण के रूप में, मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) पर भारत का स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका, एशिया और जापान (यूएनडीपी, 2014) जैसे अन्य स्थापित देशों की तुलना में काफी कम है। भारत आजादी के 68 साल बाद भी अपनी पूरी आबादी को न्यूनतम शैक्षिक स्तर नहीं दे पाया है।

भारतीय जनगणना रिपोर्ट (2011) के अनुसार, भारत में केवल 74.04% लोग साक्षर हैं। इसका मतलब है कि हमारे देश भारत में अभी भी लगभग 25.96% लोग निरक्षर हैं। इस पृष्ठभूमि में, भारत सरकार द्वारा लिया गया शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण पहल है जो 1 अप्रैल 2010 से भारतीय शिक्षा प्रणाली में गति देना शुरू कर देता है।

1.1 भारत की शिक्षा व्यवस्था

अनुसंधान और तकनीकी प्रगति सरकार के औद्योगीकरण में योगदान दे सकती है, लेकिन सीखने से सभ्यता को उसके अधिकतम स्तर तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे सूचना समाज के निर्माण और प्रबंधन की अनुमति मिलती है। कोई भी दीर्घकालिक सुधार व्यवस्थित, सर्वव्यापी शिक्षा के निर्माण का समर्थन करता है।

1.2 आर्टीई अधिनियम (2009) की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

स्वतंत्रता के बाद, नए बनाए गए संविधान के तहत अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि राज्य इस संविधान के लागू होने से दस साल की अवधि के भीतर चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 21ए (भाग III) के माध्यम से 86वां संशोधन अधिनियम (2000) 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का प्रयास करता है।

संशोधन ने एक नया अनुच्छेद 21 ए भी पेश किया, जो माता-पिता और अभिभावकों पर अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करने का कर्तव्य लगाता है। अक्टूबर, 2003 में उपरोक्त अनुच्छेद में परिष्कृत कानून का पहला मसौदा, अर्थात्, बच्चों के लिए निः

शुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक, 2003, अक्टूबर, 2003 में इस वेबसाइट पर तैयार और पोस्ट किया गया था, जिसमें बड़े पैमाने पर जनता से टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे। 2004 में, बाद में, इस मसौदे पर प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक, 2004 नामक विधेयक का एक संशोधित मसौदा तैयार किया गया था।

जून, 2005 में, CABE (केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड) समिति ने 'शिक्षा का अधिकार' विधेयक का मसौदा तैयार किया और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्तुत किया। एमएचआरडी ने इसे राष्ट्रीय सलाहकार समिति (एनएसी) को भेजा जहां श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय सलाहकार समिति (एनएसी) ने भारत के प्रधान मंत्री को उनके अवलोकन के लिए बिल भेजा। वित्त समिति और योजना आयोग ने धन की कमी का हवाला देते हुए विधेयक को खारिज कर दिया और मॉडल बिल राज्यों को आवश्यक व्यवस्था करने के लिए था (86 वें संशोधन के बाद, राज्यों ने पहले ही राज्य स्तर पर धन की कमी का हवाला दिया था)। इसे संशोधित किया गया और अगस्त, 2009 में एक अधिनियम बन गया, लेकिन लगभग 7 महीनों के लिए अधिसूचित नहीं किया गया था।

1.3 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 4 अगस्त 2009 को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। उसी के अधिनियमन ने भारत को 135 देशों में से एक बना दिया, जिसने 'शिक्षा' को मौलिक अधिकार बना दिया था। अधिनियम को 86वें संविधान संशोधन के रूप में संविधान में शामिल किया गया था।

2. बच्चे की शिक्षा में परिवार का महत्व

परिवार सबसे पुराना मानव समूह है और बुनियादी है जबकि के विशेष रूप हैं परिवार की संरचना समाज से समाज में भिन्न हो सकती है और होती है, पारिवारिक गतिविधियों का केंद्रीय फोकस हर जगह बच्चे पैदा करना और समाज में बच्चे का प्रारंभिक समावेश है। इसकी वजह है तथ्य यह है कि बच्चा परिवार से रिश्तों का आधार और मूल्य सीखता है। तभी तो वह बड़े पैमाने पर समाज, गांव और राष्ट्र का एक जिम्मेदार सदस्य बन सकता है। परिवार बच्चे को पहली शिक्षा प्रदान करता है। एक बच्चा इंसान के बारे में हर पहलू सीखता है परिवार के सदस्यों का व्यवहार। उनका व्यक्तित्व एक सरासर प्रतिबिंब और मॉडल है परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के व्यवहार के बारे में। वह संवार की कला सीखता है उसकी मां और अन्य सदस्य। व्यक्ति का व्यक्तित्व अपनी पूरी क्षमता से ही विकसित होता है यदि परिवार सभी भौतिक, नैतिक और मानसिक समर्थन प्रदान करता है। सक्रिय भागीदारी और समर्थन के बिना सरकार की कोई भी योजना फलीभूत नहीं होगी परिवार की। हो सकता है कि परिवार के सदस्य इतने निरक्षर हों कि किसी भी शिक्षा का विस्तार न कर सकें अपने बच्चों के लिए समर्थन, लेकिन वे एक आरामदायक स्थान और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं सभी स्तरों पर शिक्षा।

2.1 अध्ययन का औचित्य

संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है, "राज्य भारत की सीमाओं के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के तहत समानता या कानून के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा।" इसका मतलब यह है कि भारतीय धरती पर रहने वाले सभी लोगों की कानूनी स्थिति अन्य सभी लोगों की तरह समान है। उस समकक्ष को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा।

कानून के शासन में "कानून" शब्द का अर्थ है कि क्या वह एक आदमी या एक समाज है, वह एक आदमी या शासक द्वारा नहीं बल्कि कानून द्वारा शासित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, as भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार कानून के शासन का अर्थ है भूमि का कानून। 'कानून का शासन' और भारत जैसे लोकतांत्रिक राज्य में 'समानता का अधिकार' प्रत्येक व्यक्ति या नागरिक को जीने का अधिकार देता है बिना किसी डर या पूर्वाग्रह के समाज के किसी भी क्षेत्र में सम्मान के साथ आजादी के बाद का भारत बड़े पैमाने पर असमानता, आजीविका के साधनों की कमी और जनता के बीच गरीबी देखी गई। गरीबी उन्मूलन का अर्थ केवल सभी के लिए मुफ्त भोजन और धन का प्रावधान नहीं है राज्य और केंद्र दोनों में संबंधित सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाएं।

• प्रयुक्त शर्तों की परिचालन परिभाषा

1. स्लम बच्चे

मलिन बस्तियां शहरों के सीमांत क्षेत्र हैं जहां सुविधाएं खराब हैं, लोग निरक्षर हैं, पेयजल आपूर्ति बरबाद है। झुग्गी-झोपड़ी शहर के वो इलाके हैं जहां लोग भूखे पेट रहते हैं, कुपोषण, और विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ। दूसरे शब्दों में, मलिन बस्तियाँ के ख-डाउन क्षेत्र हैं घटिया आवास, स्वचैत, और कार्यकाल की सुरक्षा में कमी की विशेषता वाला शहर। बच्चे इन क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को स्लम चिल्ड्रन कहा जाता है।

2. कार्यान्वयन

कार्यान्वयन वह क्रिया है जिसके लिए किसी भी प्रारंभिक सोच का पालन करना चाहिए वास्तव में कुछ होने वाला है। वर्तमान संदर्भ में क्रियान्वयन का अर्थ है कि किस प्रकार से शिक्षा अधिनियम, 2009 ने स्लम के बच्चों की शिक्षा के लिए क्रियान्वित या कार्यान्वित किया है।

3. पहुंच

शिक्षा तक पहुंच सभी बच्चों की शिक्षा में समान अवसर पाने के लिए प्रवेश है, चाहे उनकी कक्षा, जाति, लिंग और जातीयता, पृष्ठभूमि, शारीरिक और मानसिक अक्षमता कुछ भी हो।

4. अवधारण

रिटेंशन का मतलब है कि स्कूल में शामिल होने के बाद, बच्चे को तब तक वहीं रहना चाहिए जब तक कि वह अपना प्राथमिक स्कूल कोर्स पूरा नहीं कर लेता।

5. रवैया

मनोवृत्ति दूसरों के प्रति किसी व्यक्ति के व्यवहार में सोचने या महसूस करने का एक स्थापित तरीका है। यहाँ पर "एटिट्यूड" शब्द का प्रयोग स्लम के बच्चों के बारे में शिक्षकों की भावना, सोच या राय जानने के लिए किया जाता है।

6. जागरूकता

जागरूकता का तात्पर्य कटक और भुवनेश्वर में प्राथमिक विद्यालयों के विभिन्न स्लम बच्चों के ज्ञान, चेतना और संज्ञानात्मक स्तर से है। हालाँकि, 'जागरूकता' शब्द का उपयोग यहाँ माता-पिता के ज्ञान को समझने के लिए किया जाता है, जैसा कि अधिनियम में अधिनियमित अपने बच्चों के अधिकार के बारे में है।

3. अध्ययन का उद्देश्य

- प्रारंभिक स्तर पर स्लम के बच्चों की पढ़ाई, नामांकन और प्रतिधारण का अध्ययन करना।
- शिक्षा के अधिकार के बारे में ओडिशा में झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों के माता-पिता की जागरूकता का अध्ययन करना अधिनियम, 2009।
- झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों की शिक्षा के बारे में माता-पिता की धारणा का अध्ययन करना।
- के कामकाज में झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों के समुदाय के सदस्यों की भागीदारी का अध्ययन करना।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के कार्यान्वयन के संदर्भ में स्कूल।
- स्लम क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा के प्रति शिक्षकों की धारणा का अध्ययन करना।
- स्लम क्षेत्रों के बच्चों के प्रति शिक्षकों के स्वयं का अध्ययन करना।
- संदर्भ में स्लम के बच्चों की शिक्षा से जुड़ी समस्याओं का अध्ययन करना शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 का क्रियान्वयन।

4. संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन

गोगोई और बेहरा (2015) ने असम के कार्बी आंगलों जिले में एक अध्ययन किया और यह पता चला कि हालाँकि आरटीई अधिनियम 2010 में लागू किया गया था, फिर भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जो अधिनियम से लाभान्वित नहीं हुए थे। अधिकांश स्कूलों में शिक्षकों को इस अधिनियम के बारे में जानकारी नहीं है। छात्र शिक्षक अनुपात आरटीई अधिनियम के मानदंडों के अनुसार नहीं है।

मोहलिक (2013) ने आरटीई अधिनियम-2009 के कार्यान्वयन में जागरूकता और चुनौतियों पर एक अध्ययन किया जिसमें उन्होंने पाया कि "सभी एचएम ने स्वीकार किया कि उन्होंने मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया है, एसएमसी का गठन किया है, स्कूल विकसित योजना तैयार की है। उनका विद्यालय।

ओझा (2013), जिन्होंने अधिनियम के मुद्दों और चुनौतियों पर एक अध्ययन किया, का कहना है कि अधिकांश स्कूलों में सभी मौसम की इमारतें और प्रधान शिक्षक के लिए एक कार्यालय सह स्टोर,

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. आचार्य, पी. यूनिवर्सल एलीमेंट्री एजुकेशन की समस्याएं आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक 29 (49): 3098-3105 (1994)

लड़कों और लड़कियों के लिए अलग शौचालय हैं। यह भी देखा गया कि स्कूल में एक अखबार आता था, लेकिन शिक्षक उसे पढ़ने से वंचित कर देते थे।

सोनी (2013) को प्राथमिक स्तर पर वंचित बच्चों के लिए आरटीई अधिनियम -2009 के कार्यान्वयन पर किए गए एक अध्ययन के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी मिली और अध्ययन से पता चला कि "नमूना राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों ने आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रावधानों को बड़े पैमाने पर लागू किया है। क्षेत्र।

आरटीई अधिनियम 2009 के लिए अग्रणी घटनाओं का क्रम

दिसंबर 2002 में 86वें संशोधन के बाद, निम्नलिखित कार्रवाई हुई:
 2003: बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा विधेयक, 2003 (एनडीए सरकार)
 2004: निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक, 2004 (एनडीए सरकार)
 2005: शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2005 जून (CABE विधेयक) (यूपीए I सरकार)
 2005: शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2005 अगस्त (यूपीए I सरकार)
 2006: केंद्रीय कानून को खारिज कर दिया गया। राज्यों को शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2006 (यूपीए-1 सरकार) के आधार पर अपने स्वयं के विधेयक बनाने की सलाह दी गई।
 2008-2009: केंद्रीय कानून को पुनर्जीवित किया गया। बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2008, लोकसभा और राज्यसभा में पेश/पास हुआ और अगस्त 2009 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई।
 हालाँकि, अधिनियम की अधिसूचना और 86वां संशोधन, भारत के राजपत्र में 19 फरवरी, 2010 को जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति की सहमति के आठ महीने बाद 1 अप्रैल 2010 से कार्यान्वयन शुरू हो जाएगा।
"शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं"

नेल्सन मंडेला

5. निष्कर्ष

शिक्षा एक मौलिक अधिकार है और हर देश में प्रगति का आधार है। माता-पिता को स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जानकारी की आवश्यकता होती है यदि उन्हें अपने बच्चों को वह जीवन देना है जिसके वे हकदार हैं। समृद्ध देश कुशल और शिक्षित श्रमिकों पर निर्भर करते हैं। आने वाले दशकों में गरीबी पर विजय पाने, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और सही मायने में सतत विकास हासिल करने की चुनौतियां हमें एक साथ काम करने के लिए मजबूर करती हैं। शिक्षा में साझेदारी, नेतृत्व और बुद्धिमान निवेश के साथ, हम व्यक्तिगत जीवन, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और हमारी दुनिया को बदल सकते हैं।

3. बोस्टोर्लोई, आर. भारत में प्रारंभिक शिक्षा में चुनौतियां: विभिन्न दृष्टिकोण। जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड प्रैक्टिस, 2(7), 39-45। (2011)
4. चौधरी, एल. ब्रिटिश भारत में प्राथमिक शिक्षा के निर्धारका। जर्नल ऑफ आर्थिक इतिहास, 69(1), 269-302 (2009)
5. चौधरी, आर. "द रोड लेस ट्रेवलेड": आर्टिकल 21ए एंड द फंडामेंटल भारत में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार (2009)
6. इंडियन जर्नल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 24, पी। 24-46. (2010) पुनःप्राप्त
7. देसाई, एफ. पी. टैगोर के शैक्षिक प्रयोग और शिक्षा का अधिकार विधेयक: एक तुलना, मानविकी में अंतःविषय अध्ययन पर रूपकथा जर्नल, 2(2): 628 - 640 (2010)
8. घोष, जे. पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन इन इंडिया, फ्रंटलाइन 28(24), 10-12. (2013)
9. गोडबोले, एम. मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा – The मुद्दे। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, XXXVI(50) (2010)
10. गोसाई, एम.आर. शिक्षा का हालिया अधिकार और प्राथमिक की वर्तमान स्थिति शिक्षा। विश्वविद्यालय समाचार, 47(47), 1-6। (2009)
11. इस्लाम, एन. और चक्रवर्ती ए स्टडी ऑन द अवेयरनेस ऑफ इक्विटेबल क्वालिटी इन द इन-सर्विस स्कूल शिक्षकों के बीच आरटीई अधिनियम '09 का प्रकाश, इंडियन जर्नल ऑफ अनुप्रयुक्त अनुसंधान, 3(6):142-143 (2013)
12. जैन, पी.एस. और ढोलकिया, आर.एच. शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सार्वजनिक – निजी साझेदारी। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, एक्सएलवी (8), 78-80 (2010)
13. जैन, पी.एस. और ढोलकिया, आर.एच. (2009)। अधिकार के कार्यान्वयन की व्यवहार्यता शिक्षा अधिनियम। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, XLIV (25), 38-43।
14. जाखड़, जे.एस. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009: मेजर की मुख्य विशेषताएं कार्यान्वयन की समस्याएं। विश्वविद्यालय समाचार, 48 (47), 06 - 12. (2010)